

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 264/2018/225 आर टी ए

सरजीतसिंह उर्फ जीतसिंह पुत्र अजमेरसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील
व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांत

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

— रेस्पोंडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 20.07.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़

प्र०सं० 08/2018 बअनवानी जसविन्द्रसिंह आदि बनाम सरजीतसिंह

उपस्थित :-

श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता अपीलांत

श्री देवदत्त भीड़ासरा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 3

सत्यमेव जयते

दिनांक:-07.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए पेश कर अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांत की खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत किये जाने अनुतोष चाहा जिसमें अप्रार्थी अपीलांत ने जवाब प्रस्तुत करते हुए तथ्यों से इन्कार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट का आवागमन कभी भी अप्रार्थी की भूमि से नहीं रहा और ना ही मौका पर कोई रास्ता चालू है और ना ही पूर्व में कभी चालू रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिन्होंने अप्रार्थी को बिना सूचना मौका रिपोर्ट पेश कर दी। जिसका ज्ञान होने पर अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पुनः रिपोर्ट अप्रार्थी की उपस्थिति में मंगवाई जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प झाम्बर में दिनांक 28.06.2018 को मौका निरीक्षण कर

निर्णय करने का आदेश दिया परन्तु दिनांक 28.06.2018 राजस्व कैम्प स्थगित होने के कारण दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर को साथ लेकर मौका निरीक्षण किया परन्तु उस जगह का मौका निरीक्षण नहीं किया जिस रास्ता से प्रार्थीगण रेस्पो० आवागमन कर रहे थे। इसके बावजूद भी दिनांक 30.06.2018 मौका निरीक्षण करने के उपरांत भी लगभग 17-18 दिन बाद रिपोर्ट अपीलांट को सूचित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के तथ्यों को सुने बिना ही उक्त पत्रावली का निर्णय करते हुए अपीलांट भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट किया जा चुका था कि रेस्पो० सं. 1 व 2 के लिए अपीलांट ने कभी भी अपनी कृषि भूमि के कि.न. 11, 20, 21 में प्रवेश नहीं करने दिया और ना ही वहां पूर्व में अथवा मौजूदा सूरत में कभी रास्ता चला और ना ही अपीलांट की भूमि में चाहा जा रहा रास्ता उनके लिए उपयुक्त है। रेस्पो० गांव झाम्बर से स्वीकृत रास्ता से होते हुए प.न. 162/300 व प.न. 161/300 प्रत्येक के कि.न. 1 ता 5 में स्वीकृत व चालू रास्ता से होकर प.न. 161/300 कि.न. 3, 8, 13 में से होकर अपनी भूमि में आवागमन कर रहे हैं और अपनी भूमि काशत करते हैं। यह भूमि रेस्पो० के परिवार वालों की है। रेस्पो० सं. 1 व 2 आरम्भ से ही इसी रास्ता से अपनी भूमि में आवागमन कर रहे हैं और यही रास्ता ग्राम झाम्बर से उनकी भूमि को जाने के लिए सुलभ और नजदीक है मात्र 8 बीघा दूरी पर है। जबकि अपीलांट की भूमि से रास्ता स्वीकृत होने पर रेस्पो० को चार मुरब्बा दूरी तय करनी होगी और वह रास्ता दूर है और सुलभ भी नहीं है। तहसीलदार द्वारा पूर्व रिपोर्ट दिये जाने के उपरांत अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र इस बाबत दिया गया कि रेस्पो० सं. 1 व 2 द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मिलकर अपीलांट को सूचित किये बिना और उसकी अनुपस्थिति में गलत रिपोर्ट पेश की है और अपीलांट की भूमि कभी भी कोई रास्ता रेस्पो० सं. 1 व 2 को अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया और ना ही मौका पर कोई रास्ता चालू है।
4. रेस्पो० गांव झाम्बर से होकर स्वीकृतशुदा रास्ता प.न. 162/300 कि.न. 3, 8, 13 में आरम्भ से ही आवागमन कर रहे हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के रीबटल में

रेस्पो० द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को विधिक रूप से कोई गौर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पुनः उक्त पत्रावली में स्वयं मौका निरीक्षण कर निर्णय करने का आदेश देने के बावजूद भी पूर्व की तरह से तहसीलदार की मार्फत पटवारी हल्का व गिरदावर से रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए निर्णय पारित किया गया है जबकि उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट की ही पुनरावर्ती की गई है। चूंकि उनके द्वारा वास्तविक भौतिक रिपोर्ट दी जानी सम्भव भी ही नहीं थी, जबकि अपीलांत के पुत्र द्वारा तहसीलदार से बार-बार निवेदन किया गया कि जिस रास्ता से रेस्पो० आवागमन कर रहे हैं उसका भी निरीक्षण किया जावे परन्तु उन्होंने कोई गौर नहीं किया और अपीलांत के पुत्र को मुगालते में रखते हुए उसके हस्ताक्षर करवा लिये और अधूरी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व रिपोर्ट की पुनरावर्ती करते हुए प्रस्तुत कर दी। इसके बाद भी अपीलांत ने दिनांक 19.07.2018 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए रिपोर्ट को गलत बतलाया और सही तथ्यों को बतलाया जिसके रीबटल में भी रेस्पो० ने कोई शपथ पत्र अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय किये जाने में कानूनी भूल की है। रेस्पो० सं. 1 व 2 अपीलांत की भूमि में से जबरन रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु बजिद है जबकि उन्हें अपनी भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता है जिससे वे आवागमन कर रहे हैं और विचारण न्यायालय के समक्ष ये तमाम तथ्य पत्रावली पर थे परन्तु विचारण न्यायालय ने उन पर गौर किये बिना और सम्यक रूप से अपने निर्णय में विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो० सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प. न. 161/292 मु.न. 16 के कि.न. 6, 7, 8 की कुल 0.759 है० है। उक्त भूमि के चिपते ही अपीलांत के नाम से चक 7 एसएसडब्ल्यू में 4.491 है० भूमि है उक्त भूमि के प.न. 161/392 मु.न. 16 के कि.न. 3, 4, 5 में दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है व रेस्पो० उक्त स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 में उतर से दक्षिण दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया

गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अलावा प.न. 161/292 मु.न. 16 कि.न. 3, 8 के पश्चिम दिशा व कि.न. 8 मे दक्षिण दिशा अर्थात तीन बीघा जो रास्ता देने सहमति प्रदान की गई जिससे यह साबित हो जाता है कि रेस्पो० सं. 1 व 2 को अपनी खातेदारी भूमि के लिए कोई रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय वैकल्पिक रास्ता दिया जाना उचित नहीं मानते हुए प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत किया गया जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो० सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये अप्रार्थी/अपीलांट की भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू के प.न. 161/392 के मु.न. 16 के कि.न. 5 मे उतर से दक्षिण दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। न्याय आपके द्वार कैम्प दिनांक मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने हेतु तहसीलदार को आदेश दिया गया जिस पर दिनांक 30.06.2018 को तहसीलदार द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन आदेश के संबंध मे अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि “ रेस्पो० गांव जाम्बर से स्वीकृत रास्ता से होते हुए प.न. 162/300 व प.न. 161/300 प्रत्येक के कि.न. 1 ता 5 मे स्वीकृत व चालू रास्ता से होकर प.न. 161/300 कि.न. 3, 8, 13 मे से होकर अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है और अपनी भूमि काशत करते है। यह भूमि रेस्पो० के परिवार वालो की है। रेस्पो० सं. 1 व 2 आरम्भ से ही इसी रास्ता से अपनी भूमि मे आवागमन कर रहे है रेस्पो० के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता यही है। रेस्पो० की भूमि पूर्व मे संयुक्त खाता मे थी व उसी मे रास्ता स्वीकृत किया जावे जिसके संबंध मे अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जमाबंदी चक 7 एसएसडब्ल्यू खाता सं. 117/112, खाता सं. 107/97, खाता सं. 126/25, खाता सं. 112/54, 44/54, जमाबंदी चक 10 केएसपी के खाता सं. 119/105, 99/87, चक

7 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 67/64 आदि प्रस्तुत किये। परन्तु उक्त दस्तावेजात से वादग्रस्त भूमि के संबंध में बंटवारा/विभाजन होना सिद्ध नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त संयुक्त खाता की भूमि बाबत बंटवारा/विभाजन होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिवक्ता अपीलांत के तर्क मानने योग्य नहीं है। तहसीलदार की रास्ते बाबत मौका निरीक्षण रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार रेस्पो0 को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ता दिया जाना उचित है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथा प्रकरण में तहसीलदार स्वयं द्वारा किये गये मौके निरीक्षण से यह साबित होता है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में पूर्व में तहसीलदार से रास्ता के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई उसके पश्चात कैम्प कोर्ट अभियान के दौरान पक्षकारों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश से उचित रास्ता स्वीकृत किया है।

7. हस्तगत प्रकरण में रास्ता भूमि के बदले जमीन दी जाने संभव है तथा जहां तक रास्ता की जगह में फसल काश्त, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि होने का प्रश्न है तो रास्ता राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 2012 के नियम 70 (2) के प्रावधानों के अनुसार रास्ता में प्रयुक्त होने वाली भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये रास्ते में फसल या पेड़ आदि को हटाने के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा की राशि का निर्धारण कर रास्ते की भूमि के खातेदार को दिलाया जाना आज्ञापक है। प्रस्तुत प्रकरण में रास्ते में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र के मुआवजे के संबंध में बराबर क्षेत्र की भूमि दिया जाना संभव होने की स्थिति में चिपती हुई भूमि दिये जाने के आदेश किया है एवं फसल काश्त, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि के मुआवजे संबंधी कोई आदेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में वर्णित मुआवजा संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज में चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य में स्थित फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु खेजडी के पेड़ों की कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाने उचित होने के कारण फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं

नक्का आदि की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि का निरीक्षण कर कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांट को दिलवाई जाने उचित है। निर्णय की प्रति तहसीलदार को फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं नक्का आदि की कीमत का भुगतान करने हेतु प्रेषित की जावें।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 में वर्णित मुआवजा संबंधी आदेश में संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज में चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पोंडेंट सं. 1 व 2 द्वारा अपीलांट को दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य में फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना का निरीक्षण आज दिनांक से 15 दिवस की अवधि में करते हुए कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांट को दिलवाई जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को फसल, खेजडी के 8-10 शिशु पेड़ एवं अन्य संरचना की कीमत का भुगतान उक्त वर्णित अनुसार करने हेतु प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2018 में वर्णित केवल मुआवजे संबंधी संशोधन करते हुए शेष यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़